viewed as a non-partisan agency." This is why the Supreme Court had said, 'you make the CVC a statutory authority, which will oversee all investigations of CBI'. So, when the Government is not granting sanctions, the CVC will ensure that sanction is granted and the case is proceeded, and this is why I am putting this question. It is directly related to the question that I have already put. So, will the hon. Minister respond to it?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Sir, even now, the CVC reviews the overall functioning of vigilance administration and mechanism of the Government Departments to include sanctions pending with various competent authorities, for sanction of prosecution. It has advised the administrative Ministries/Departments to refer such cases to CVC within 30 days from the date of receipt of the report from CBI. Hence, sanctions for prosecution are being reviewed by CVC regularly. This is how I have understood the question.

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, I think I have not been able to deliver the point. I would request the hon. Minister to, at least, respond to me in writing, at a later point of time, as to what is the commitment of the Government on the constitution of a statutory authority.

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक खास केस के बारे में पूछना चाहूंगा?

श्री सभापति: आप खास केस के बारे में मत पूछिए।

श्री संजय निरूपम: नहीं पूछ सकता तो मैं बैठ जाता हूं।

**323. [The questioner (Shri Vijay J. Darda) was absent. For answer vide page 38.]*

**324. [The questioner (Shri Bachani Lekhraj) was absent. For answer vide page 40.]*

Revenue sharing between BSNL and VSNL

*325. SHRI GAYA SINGH†:
SHRI V.V. RAGHAVAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether an agreement has been reached between BSNL and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gaya Singh.

VSNL over the revenue sharing formula in International Long Distance (ILD) services; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) BSNL and VSNL have signed an agreement over the sharing of revenue in International Long Distance (ILD) services on 18th November, 2002. This agreement provides for sharing of revenue between BSNL and VSNL from international long distance traffic based on distance and volume from 1st August, 2002 to 31st March, 2003.

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, इन्होंने जवाब में कहा है कि हमने आठ महीने का एग्रीमेंट किया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इतने कम समय के लिए एग्रिमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि यह अगस्त से लेकर मार्च तक है। दूसरे इसमें उन्होंने इतना ही कहा है कि एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट से आगे के लिए लांग डिसटेंस के शेयर करने वाले होंगे, उनके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी नियुक्त की है?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, जब तक वी॰एस॰एन॰एल॰ का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, 1997 से 31 मार्च 2002 तक डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्यूनिकेशन और वी॰एस॰एन॰एल॰ में एक इन्टरकनेक्ट एग्रीमेंट था जिसके अनुसार पैसे का बंटवारा होता था। वी॰एस॰एन॰एल॰ को फरवरी में टाटा को बेचे जाने के बाद, 1 अप्रैल, 2002 से नए एग्रीमेंट बनाने की जरुरत थी उसमें नियम यह था कि बाजार में बाकी कंपनियां जिस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं उसके अनुसार ही यह एग्रीमेंट बने। क्योंकि बाजार निर्धारित अगस्त से हुआ, जब अगस्त में तीन प्राइवेट प्लेयर आए। इसलिए अगस्त से मार्च तक एग्रीमेंट हुआ है। पहला एग्रीमेंट। अप्रैल से अगस्त तक लागू करने के लिए कहा है। जहां तक दूर तक काल करने का सवाल है, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इसके भाव इतने बदलते रहते हैं कि बहुत दूर तक वी॰एस॰एन॰एल॰ के साथ अगर एग्रीमेंट किया जाए तो उससे बी॰एस॰एन॰एल॰, एम॰टी॰एन॰एल॰ को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि 31 मार्च, 2003 तक एग्रीमेंट करें और उसके अनुसार जैसे ही नई परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार हम नया एग्रीमेंट करेंगे।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, एक संदेह व्यक्त हो रहा है क्योंकि मंत्री जी ने मार्च तक कहा है और मार्किट देखने के बाद आगे की बात करेंगे तो क्या इसको आगे निजीकरण की ओर ले जाने की भी सरकार की मंशा है?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, इस प्रश्न का इससे सीधे संबंध नहीं है लेकिन निकट भविष्य में भारत संचार निगम और महानगर टेलीफोन निगम का निजीकरण होने की कोई संभावना नहीं है।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, our experience shows that private operators who enter into agreement with the Department of Telecom, do not fulfil their agreements. Though bank guarantees have been given, nothing is being done to recover the amount from defaulters. I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken by the Government to ensure that these agreements are fulfilled by the private operators.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, private operators, in ILD sector, have been working since August, and they are making payments regularly. So, there is no question of private operators being defaulters, at this stage. As far as the VSNL is concerned, as I said, the agreement has been signed recently. We don't have any apprehension on VSNL, not paying money to us. At the same time, the Government has still 26 per cent of equity in that company. So, there is no question of VSNL being a defaulter, as far as BSNL or MTNL is concerned. If they become defaulters, we will take appropriate action, which is permissible under the law.

**326. [The questioner (Shri Harendra Singh Malik) was absent. For answer vide page 41.]*

राष्ट्रीय राजमार्ग - 83

*327. **श्री लालू प्रसाद:**
श्री विजय सिंह यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 के जहांनाबाद से डोभी तक के खंड की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त खंड के संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्रवाई करने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक?